नवभारत टाइम्स

DU: साइबर सिक्यॉरिटी इंस्टिट्यूट अगले साल

कात्यायनी उप्रेती, नवभारत टाइम्स| Oct 28, 2017, 09.30 AM IST

दिल्ली यूनिवर्सिटी का 'इंस्टिट्यूट ऑफ साइबर सिक्यॉरिटी ऐंड लॉ' इस साल लॉन्च नहीं हो पाएगा। यूनिवर्सिटी को पूरी उम्मीद थी कि इस नए प्रॉजेक्ट के लिए सितंबर से ऐडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मगर तैयारियां पूरी नहीं हो पाईं। यह इंस्टिट्यूट जनवरी तक के लिए टल गया है, जिसकी एक बड़ी वजह यूजीसी से मंजूरी न मिलना भी बताई जा रही है। इसके अलावा साइबर सिक्यॉरिटी के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी का इंतजाम भी बाकी है। प्रशासन का कहना है कि यूजीसी से अगर नवंबर तक भी मंजूरी मिल जाती है तो जनवरी से पहला सेशन लॉन्च करके इसे दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा और इस हिसाब से इंस्टिट्यूट एक सेशन लेट नहीं होगा। अगर इजाजत नहीं मिली तो यह एक साल का एक्सपर्टाइज कोर्स एक सेशन तक लेट हो सकता है।

डीयू के वीसी प्रो योगेश त्यागी का साइबर सिक्यॉरिटी का यह ड्रीम प्रॉजेक्ट इस साल सितंबर में शुरू होने वाला था। प्रो त्यागी का कहना है कि इस कोर्स को इसलिए लाया जा रहा है ताकि डीयू से इंटरनैशनल मार्केट को साइबर सिक्यॉरिटी एक्सपर्ट्स मिलें। मगर जिस इंस्टिट्यूट के लिए प्रशासन अगस्त लास्ट में नोटिफिकेशन लाने वाला था, उसके इस साल अब शुरू होने की उम्मीद नहीं है। डीयू प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी बताते हैं, इस इंस्टिट्यूट के तहत एक साल का पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स चलना है और यह एक्पर्टाइज कोर्स है, जिसे शुरू करने के लिए फूलप्रूफ तैयारी चाहिए।

एग्जिक्युटिव काउंसिल से जून में मंजूरी

इंस्टिट्यूट के तहत 'पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्यॉरिटी और लॉ' प्रोग्राम चलाने का प्लान है। इसे यूनिवर्सिटी की एग्जिक्युटिव काउंसिल से जून में ही मंजूरी मिल चुकी है। इंस्टिट्यूट की ओएसडी डॉ. सुनैना कनौजिया कहती हैं, इसके लिए हम अभी यूजीसी से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर का इंतजाम करना है। लैब में सभी सॉफ्टवेयर सेट करने में भी कुछ वक्त लगेगा। कई आईटी कंपनियों के एक्सपर्ट अधिकारी, सीईओ यहां पढ़ाने पहुंचेंगे, इनका शेड्यूल करना भी बड़ा चैलेंज है। हमारी पूरी कोशिश है कि क्लासेज फरवरी से शुरू कर दी जाएं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि फरवरी और मार्च में आईटी कंपनियों के बड़े अधिकारियों का बिजी शेड्यूल रहता है, ऐसे में इस वक्त क्लासेज होना मुश्किल हो सकता है। ओएसडी कहती हैं, अगर यूजीसी से जल्द मंजूरी मिल जाती है, तो हम यह कोर्स जनवरी 2018 से शुरू करके दिसंबर 2018 तक पहले बैच के साथ चलाएंगे। दूसरे बैच के लिए हम जुलाई से प्रोसेस शुरू करके इसे 2019 तक चलाएंगे। इस हिसाब से इसी साल दो बैच चलेंगे।

प्राइवेट के मुकाबले पांच गुना कम होगी फीस

कोर्स सेल्फ फाइनेंस होगा। ओएसडी बताती हैं, प्राइवेट इंस्टिट्यूट में इस कोर्स की फीस ढाई से तीन लाख है, मगर डीयू में यह इससे करीब पांच गुना कम होगी। डीयू का अब तक का प्लान है कि इस कोर्स के लिए ऐडमिशन मेरिट और इंटरव्यू बेसिस पर होगा। प्रशासन का कहना है कि हम अधूरी तैयारी के साथ इंस्टिट्यूट को लॉन्च नहीं करना चाहते हैं और इस साल अब वक्त नहीं बचा है इसलिए हमारा प्लान है कि जनवरी से इसे शुरू किया जाए।